PRESS MONITOR

Business Standard, Delhi

Thursday, 10th March 2011, Page: 6

Width: 25.37 cms Height: 9.30 cms, Ref: pmin.2011-03-10.44.47

Realtors' body wants to change perceptions

BS REPORTER
New Delhi, 9 March

Real estate developers are trying to change perceptions. A new team of office bearers which took charge at the Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (Credai) will work on a set of measures that will help builders deliver projects on time, redress customer grievances and improve governance to change image and perception of the industry.

Credai, with 6,000 developers as members, will like to work with the government to create a complete checklist for all clearances required, and facilitate a single-window clearance for projects. "If this happens, we can save 20 per cent cost in metros and 8-10 per cent in tier II and III cities," said Credai National President Lalit Kumar Jain.

Developers say today it takes around 9-10 months to secure 40-odd clearances from different government departments. Next, Credai wants to set up consumer redressal cells in every state to address consumer disputes. Such cells have already come up in Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh and Kerala. "Such disputes can be resolved amicably in 60 days; there's no need to go to the courts," said Jain.

CREDAI WANTS TO set up consumer redressal cells in every state to address consumer disputes. Such cells have already come up in Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh and Kerala

Credai member associations have adopted a code of conduct, which will be signed by every developer. The developers' body wants to create a research cell for affordable housing strategy, technology and funding and work with the government. It has taken an initiative to bring all cities of more than 500,000 population into Credai's fold. It will also widen its membership base, and get members from eastern and central India.

Parsvnath Chairman Pradeep Jain, who was elected as Credai Chairman said, "With support from government and reduction in interest rates, demand for affordable housing is likely to grow at 13 per cent in the next two years. The future lies in tier II and tier III cities; they will be the centre of attraction in the real estate market," he said.

PRESS MONITOR

Jansatta, Delhi

Thursday, 10th March 2011, Page: 10

Width: 17.27 cms Height: 11.90 cms, Ref: pmin.2011-03-10.43.62

आचार संहिता अपनाएंगी रीयल एस्टेट कंपनियां

नई दिल्ली, 9 मार्च (भाषा)। रीयल एस्टेट कंपनियों को शिकायत है कि बजट में रियायत संबंधी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें यह भी लगता है कि ऐसा संभवतः उनकी छवि के कारण है क्योंकि उन्हें फ्लैट के घोषित मूल्य और मानकों को बदल कर येन केन प्रकारेण मुनाफाखोरी करने वालों वालों के रूप में देखा जाता है। ऐसे में अब ये कंपनियां अपने संगठन क्रेडाई के बैनर तले अपनी छवि सुधारना चाहती हैं और क्रेडाई के सदस्य एक आचार संहिता अपनाएंगे।

पार्श्वनाथ डेवलपर्स के प्रमुख और क्रेडाई के नवनियुक्त चेयरमैन प्रदीप जैन ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि हम चाहते हैं कि डेवलपर्स के प्रति धारणा बदली जाए। उन्होंने कहा कि बिल्डरों का देश के विकास में काफी योगदान है, इसके बावजूद उनके प्रति सरकार का रुख सही नहीं है। क्रेडाई का मानना है कि बिल्डरों के प्रति लोगों के साथ-साथ सरकार की राय भी अच्छी नहीं है। यही वजह है कि बजट पूर्व चर्चा में क्रेडाई की मांगों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है।

क्रेडाई के नवनियुक्त अध्यक्ष ललित कुमार जैन ने कहा कि अचल संपत्ति विकसित करने वाली कंपनियों के प्रति धारणा में बदलने के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि व्यावसायिक और आवासीय सभी तरह की परियोजनाओं में कीमतों में स्पष्टता हो। उन्होंने कहा कि क्रेडाई के सभी सदस्यों को एक आचार संहिता पर दस्तखत करने होंगे। इसके अलावा सभी शहरों में उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।

जैन ने बताया कि फिलहाल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और केरल में ऐसे शिकायत निपटान प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं, जहां कोई भी खरीदार किसी भी डेवलपर कंपनी के खिलाफ पांच सौ रुपए का शुल्क देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसकी शिकायत पर जांच कर उसका निवारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे सदस्यों को आचार संहिता पर भी दस्तखत करने होंगे। क्रेडाई के सदस्यों की संख्या छह हजार से अधिक है।

जैन ने कहा कि हम कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्रेडाई का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित इमारतों पर ध्यान केंद्रित करना और कम बिजली खपत वाली इमारतें बनाना है।

PRESS MONITOR

Hindustan, Delhi

Thursday, 10th March 2011, Page: 13

Width: 12.87 cms Height: 7.20 cms, Ref: pmin.2011-03-10.47.45

फ्लैट होंगे महंगे, बढ़ेगी सस्ते घरों की मांग

जमीन व सीमेंट के दाम में हो रही वृद्धि के कारण फ्लैटों की कीमत बढ़ा रही हैं कंपनियां.

एजेंसियां

नई दिल्ली

निर्माण की बढ़ती लागतों की दुहाई देते हुए रीयल एस्टेट कंपनियों का कहना है कि घरों की कीमतों में आने वाले समय में और तेजी आएगी। उनका कहना है कि जमीन और सीमेंट आदि के दाम चढ़ रहे हैं। पार्श्वनाथ डेवलपर्स के प्रमुख एवं रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई के चेयरमैन प्रदीप जैन ने कहा कि आवासीय वर्ग में कीमतों में ऊपर की ओर जाने का रुख बना हुआ है। जैन ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बाद रीयल एस्टेट क्षेत्र में दाम जरूर नीचे आए थे, पर अब तमाम तरह के शुल्कों के साथ सीमेंट आदि कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए कहा जा सकता है कि घरों के दाम ऊपर की ओर चढ़ेंगे।

क्रेडाई का अनुमान है कि सरकार के इस कदम से सस्ते घरों की मांग बढ़ेगी। 2011 से 2013 के दौरान सस्ते घरों की मांग में सालाना 13 फीसदी की दर से बढ़ोतरी होगी। जैन ने कहा कि जहां तक वाणिज्यिक संपत्ति की बात है, तो उनकी आपूर्ति मांग की तुलना में अधिक है। ऐसे में व्यावसायिक संपत्तियों के दामों में शहर दर शहर के हिसाब से बदलाव आएगा।

Business Line, Delhi

Thursday, 10th March 2011, Page: 9

Width: 4.49 cms Height: 13.19 cms, Ref: pmin.2011-03-10.31.77

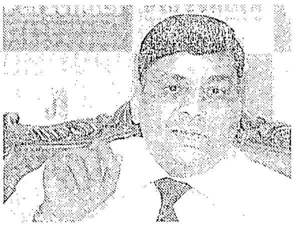

Mr Pradeep Jain

Credai elects new Chairman

Our Bureau

New Delhi, March 9

The Confederation of Real Estate Developers' Association of India (Credai) has elected Parsvnath Chairman, Mr Pradeep Jain, as the new Chairman of the industry body.

Mr Lalit Kumar Jain, Chairman of Kumar Urban Development Ltd, has also been elected as the President of Credai national. Speaking to reporters after being elected as the new Chairman of Credai, Mr Pradeep Jain said the association would take up with the government various issues such as tax sops and priority lending to buyers as well as builders in the affordable housing segment.

PRESS MONITOR

The Economic Times, Delhi

Thursday, 10th March 2011, Page: 15

Width: 6.01 cms Height: 6.56 cms, Ref: pmin.2011-03-10.34.87

Realtors Demand Single-Window Clearance

NEW DELHI CREDAI, the apex industry body for real estate developers, today sought single-window clearance to prevent project delays and to bring down housing prices. Speaking to reporters after being elected as the new Chairman of CREDAI, Parsvnath Developers Chairman Pradeep Jain said the association would take up with the government issues like single-window clearance, tax sops and priority lending to buyers as well as builders in the affordable housing segment. "Our vision is to bring CREDAI at par with other business chambers. We need to work hard with the government for changing the perception about the industry," Jain said.